मजदूरों का अपना कोई देश नहीं होता ।

दुनियां के मजदूरो, एक हो !

फरीदाबाद मजदूर समाचार

मजदूरों की मुक्ति खुद मजदूरों का काम है ।

दुनियां को बदलने के लिए मजदूरों को खुद को बदलना होगा ।

RN 42233 पोस्टल रजिस्ट्रेशन L/HR/FBD/73

नई सीरीज नम्बर 45 | मार्च 1992 | 50 पैसे

बजट

राजीव गाँधी के वित्तमंत्री वी. पी. सिंह की राह पर नरसिम्हा राव के वित्तमंत्री मनमोहनसिंह तेजी से आगे बढ़े हैं। दीर्घकाल से पूँजी के वाम और दक्षिण धड़ों के अर्थ-शास्त्री जिन नुस्खों को राम बाण पेश कर रहे थे उन सब को रिजर्व बैंक के गवरनर रह चुके मनमोहन सिंह ने अपने पिटारे में जगह दे दी है। वी. पी. की शहीद की मुद्रा मनमोहन सिंह की सरफरोशी की तमन्ना के सम्मुख फीकी पड़ गई है। समवेत स्वर में पूँजीपति वर्ग मनमोहन सिंह के जयकारे लगा रहा रहा है - अडवाणी - ज्योति बसु-इण्डियन एक्सप्रैस बगलें झांक रहे हैं।

विश्व पूँजी की भारतीय इकाई के लिए इस मनमोहक बजट से बेहतर बजट इस समय शायद ही बन पाता। पूँजीवादी विद्वता यहाँ अपनी सीमा को छू रही है। और यही वह स्थान है जहाँ पूँजीवादी व्यवस्था का दिवालियापन एक और विद्वान वित्तमन्त्री की कूपमडूकता के रूप में प्रदर्शित हो रहा है। अन्य वित्त-मन्त्रियों की ही तरह श्री मनमोहन सिंह भी यह समझने में अक्षम हैं कि उत्पादक शक्तियां जिन स्तरों में दाखिल हो गई हैं वहां माल उत्पादन, मंडी के लिए प्रोडक्शन एक नकारा खोल बन गया है। यह हकीकत स्वयं को पूँजी-वादी व्यवस्था के संकटों, गहराते संकटों के रूप में प्रदर्शित कर रही हैं। और मानवों के बढ़ते दुख-दर्द इसकी कीमत हैं। माल उत्पादन, पूँजीवादी माल उत्पादन मानवद्रोही बन गया है। यह इसीलिए है कि पूंजीवादी तालियों की गड़गड़ाहट के बावजूद मनमोहनसिंह के नुस्खे टोटके हैं और टोटके ही साबित होंगे।

पूंजीवादी व्यवस्था के गहराते संकट की वजह से पूर्व-पूर्वी यूरोप आदि में राज्य पूँजीवादी किलों में पड़ी दरारों को आमतौर पर पूँजीवादी प्रचार समाजवाद की हार तथा पूंजीवाद की जीत पेशकर रहा है। पूंजीवादी व्यवस्था के गहराते संकट के एक अन्य लक्षण, मन्दी के भंवर में फंसे अमरीकी उद्योग/डूब रहे अमरीकी बैंकों का अर्थ तक समझने से आमतौर पर पूंजीवादी विद्वान इनकार कर रहे हैं। पर हकीकत हैं कि आंख चुराने से गायब नहीं हो रहीं। दुनिया - भर में गहराती मन्दी के रूप में पूंजीवादी व्यवस्था का संकट इस समय बढ़ता जा रहा हैं। औद्योगिक उत्पादन में आमतौर पर ठहराव/गिरावट के रुझान ने उत्पादन इकाइयों में चौतरफा होड़ को काफी तेज कर दिया है। और चूंकि अब कुल मिलाकर उत्पादन इकाइयां देशों के रूप में संगठित हैं, इसलिए प्रत्येक देश की सरकार अपने उद्यमों को होड़ में शक्तिशाली बनाने के लिए ताबड़तोड़ कदम उठा रही है। रूस चीन आदि की सरकारों की ही तरह भारत सरकार भी अब समाज-वाद वगैरह को खूंटी शर टांग कर खुलेआम ऐसा कर रही है। मनमोहनसिंह का बजट इसकी बोलती मिसाल है।

देशभक्ति की अफीम, डंडे के डर लालच आदि के जरिये हर देश में छँटनी, वर्क लोड में वृद्धि, वेतन सहूलियतों में कटौती का आम महौल हैं। लेकिन फिर भी संकट है कि चौतरफा फैल रहा है, बढ़ रहा है, रहा है। इसकी वजह से शान्ति अहिंसा के नारों के बावजूद हथियारों में, फौजों में तेजी से वृद्धि हो रही है।

प्रत्येक देश में इस प्रकार बढ़ रहा है उत्पादन साथ ही साथ संकटों को भी बढा रहा है। दरअसल यह संकट उत्पादन बढाने की भौतिक दिक्कतों की वजह से नहीं है। बेरोजगारों की बढती फौजें, ठाली पड़ी मशीनें, ढेरों में बरबाद होते कच्चे माल (अमरीका में खेत पड़त छोड़ने के लिये सरकार सब्सीडी देती है ; पश्चिमी यूरोप में मक्खन के पहाड़ लगने, भाव गिरने के विरोध में लाखों दुधारू गायों को मौत के घाट उतारने की बातें होती हैं)—यह सब इस बात का सबूत हैं कि समस्या भौतिक उत्पादन की नहीं बल्कि सामाजिक है। और यह समस्या है पूंजी वाला सामाजिक सम्बन्ध, पूँजीवादी व्यवस्था।

पूँजीवाद के स्थान पर मानव हित में आज जरूरत है देशों को तोड़ कर विश्व मानव समुदाय के गठन की, साम्यवादी समाज की स्थापना की। लेकिन हर सरकार का बजट देश की एकता और अखण्डता की रक्षा के लिए आड़ तलाशता है। वैसे वर्तमान हकीकत से मजबूर मनमोहनसिंह द्वारा मौजूदा विश्व व्यवस्था में भारत की भूमिका उभारने की कोशिशों के खिलाफ स्वयं को प्रगति-शील, वामपंथी कहने वालों द्वारा "देश की सम्प्रभुता को गिरवी रखने—देश की आत्म निर्भरता की राह छोड़ने" वाली चिल्ल-पो, इन लोगों के मनमोहनसिंह से भी प्रतिक्रियावादी होने की घोषणा है।

अडवाणी और ज्योति बसु एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। लेकिन ज्योतियों ने मजदूर पक्ष के उभरने की राह में बड़े रोड़े बनकर पूंजी की सुरक्षा में विशेष योगदान दिया है। इनकी करतूतें भी काफी हद तक इस स्थिति के निर्माण में सहायक रही हैं जहां बढ़ते पूँजीवादी हमलों के सामने आमतौर पर मजदूर हाथ पर हाथ धरे समर्पण कर रहे हैं। मनमोहनसिंह के बजट का बराये नाम का विरोध करके सी पी आई - सी पी एम आदि मजदूरों को गुमराह करने की अपनी हैसियत को बनाये रखने की कोशिश कर रही हैं। पूंजी-वादी गुटों के झगड़ों में साम्राज्य-वाद-विरोध आदि के नाम पर, देशी विदेशी के नाम पर मजदूरों को इस्तेमाल करने के लिए राज्य-पूँजी-वाद की पक्षधर धाराएँ अभी काफी कोशिशें करेंगी।

दुख-दर्द से छुटकारा पाने के लिए क्रान्तिकारी मजदूर आन्दोलन का विकास सर्वोपरि कार्य हैं। इसके लिये जरूरी हैं कि मजदूर जाति धर्म-भाषा-इलाके आदि की बेड़ियों को तो पहचाने व तोड़ने की कोशिशें करें ही देशभक्ति की पूंजीवादी अफीम को भी मजदूर पहचानें व ठुकरायें।

कटलर हैमर

जड़ कुछ और है

मथुरा रोड स्थित कटलर हैमर की मुख्य फैक्टरी में 24 फरवरी को टूल डाउन हुआ। 25-26 फरवरी को टूल डाउन जारी रहा। 27 फरवरी को मैनेजमेंट ने कुछ बातों पर दस्तखत करने के बाद फैक्ट्री के अन्दर जाने की शर्त रखी। मजदूरों ने इस शर्त को नहीं माना। मैनेजमेंट ने पुलिस बुला रखी थी। पुलिस का इस्तेमाल करके मैनेजमेंट ने मजदूरों को फैक्ट्री गेट के बाहर रोक दिया। इस प्रकार कोई प्रकार कोई चाहे तो 27 फरवरी से कटलर हैमर के 831 मजदूरों को हड़ताल पर कह सकता हैं।

एक्सीडैन्ट में किसी मजदूर की मौत होने पर उसके परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने की मांग मैनेजमेंट द्वारा नहीं मानने को 24 फरवरी की टूल डाउन का कारण बताया जा रहा है। इस मांग के उठने का कोई तात्कालिक अथवा विशेष कारण नहीं है। एक सामान्य मांग को अचानक तूल देने के पीछे कारण दूसरे ही लगते हैं। कटलर हैमर में मजदूर पक्ष की कमजोरी दूर करने, मज-को ताकत बढ़ाने के लिए कदम तय करने वास्ते काफी कुछ जानने की जरूरत है। ऐसी जानकारी अन्य मजदूरों के लिए भी उपयोगी रहेगी। इसलिए हम कटलर हैमर के इस घटनाक्रम पर कुछ विस्तार से विचार करेंगे।

सीमेन्स, लार्सन एण्ड ट्यूब्रो, कटलर हैमर, टेलेमैकेनिक, इंगलिश इलैक्ट्रिक, कन्ट्रोल्स एण्ड स्विचगियर भारत में इलैक्ट्रिक कन्ट्रोल सिस्टमस क्षेत्र की प्रमुख कम्पनियाँ हैं। इनमें से कटलर हैमर, लार्सन एण्ड ट्युब्रो, इंगलिश इलैक्ट्रिक तथा कन्ट्रोल एण्ड स्विचगियर वे कम्पनियाँ हैं जो भारत में उत्पादन करके बिक्री करती है। सीमेन्स कम्पनी उत्पादन यहां भी करती है और सीमेन्स की अन्य देशों में स्थित फैक्ट्रियों से माल यहाँ मंगाती भी है। टेलेमैकेनिक कम्पनी अन्य देशों में स्थित अपनी फैक्ट्रियों के उत्पादन को यहाँ बेचती है। मोटे तौर पर की गई यह तीन कैटेगरियां आजयहां महत्वपूर्ण बन गई हैं।

साल भर मे विदेशी मुद्रा की अत्यधिक तंगी की वजह से सरकार द्वारा बाहर से माल मंगाने पर लगाए कठोर नियंत्रणों ने कटलर हैमर वाली कैटेगरी की कम्पनियों को उछाल रखा था। कटलर हैमर में पिछले कुछ महीनों में हुए लगातार ओवरटाइम का एक प्रमुख कारण वह सरकारी पालिसी थी। विदेशी मुद्रा की स्थिति में सुधार होने पर सरकार ने बाहर सामान मंगाने में छूट देनी आरम्भ की। कटलर हैमर वाली कैटेगरी की नोएडा स्थित कन्ट्रोल्स एन्ड स्विचगीयर कम्पनी इस वजह में लड़खड़ाने लगी। और फिर, आने वाले बजट की तस्वीर अन्यों को भी दिखने लगी थी। ऐसे में कटलर हैमर जैसी मैनेजमेंण्टों के लिए टिके रहने के वास्ते तेजी से नई स्कीमें बनाना जरूरी हो गया। इन मैनेजमेंटी की ऐसी स्कीमों का एक ही अर्थ है - क्वालिटी सुधारना तथा लागत कम से कम करना। मजदूरों के लिए इसका मतलब हैं छँटनी, वर्कलोड में वृद्धि, सहुलियतों में कटौती और वेतन में कमी।

घटनाक्रम के कुछ और महत्वपूर्ण पहलू भी हैं :

मन्दी के लक्षण आज हर देश में नजर आ रहे है। भारत में पिछले साल औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि की बजाय कमी आई है। मन्दी ने दुनिया-भर में कार्यरत फैक्ट्रियों के बीच होड़ को तेज कर दिया है। भारत में घाटे की वजह से उत्पादन क्षेत्र में कम धन लगाने के सरकार के फैसले ने यहाँ मण्डी को और सिकोड़ा है। इस बजट में बाहर से

(शेष पृष्ठ २ पर)

हमारे लक्ष्य हैं:— 1. मौजूदा व्यवस्था का बदलने के लिये इसे समझने की कोशिश करना और प्राप्त समझ को ज्यादा से ज्यादा मजदूरों तक पहुंचाने के प्रयास करना। 2. पूंजीवाद को दफनाने के लिए जरूरी दुनियां के मजदूरों की एकता के लिये काम करना और इसके लिये आवश्यक विश्व कम्युनिस्ट पार्टी बनाने के काम में हाथ बटाना। 3. भारत में मजदूरों का क्रान्तिकारी संगठन बनाने के लिये काम करना। 4. फरीदाबाद में मजदूर पक्ष को उभारने के लिये काम करना।

समझ, संगठन और संघर्ष की राह पर मजदूर आन्दोलन को आगे बढ़ाने के इच्छुक लोगों को ताल-मेल के लिये हमारा खुला निमन्त्रण है। बातचीत के लिये बेझिझक मिलें। टीका टिप्पणी का स्वागत है—सब पत्रों के उत्तर देने के हम प्रयास करेंगे।

संपर्क - मजदूर लाइब्रेरी, आटोपिन झुग्गी, बाटा चौक के पास, एन. आई. टी. फरीदाबाद121001

तालाबन्दियाँ.....

भारत स्टील ट्यूब्स, गन्नौर (सोनीपत) में तालाबन्दी को सालों हो गये हैं.....

के. जी. खोसला कम्प्रेसर, फरीदाबाद में तालाबन्दी को छह महीनों से ज्यादा हो गये हैं ...

मोहन स्पिनिंग मिल रोहतक में तालाबन्दी को तीन महीनों से ज्यादा हो गये हैं।

बिड़ला ग्रुप की भिवानी स्थित टैक्सटाइल मिल में १७ फरवरी से तालाबन्दी जारी है

हरियाणा प्रान्त के ही अलग-२ जिलों में तालाबन्दियों के यह कुछ उदाहरण मात्र हैं। पर तालाबन्दी हरियाणा की विशेषता नहीं है। बम्बई में हिन्दुस्तान लीवर के मजदूर हों चाहे कलकत्ता में बाटा के मजदूर, तालाबन्दी से सब जगह मजदूरों का पाला पड़ रहा है। आज मजदूरों पर पूंजीवादी हमलों में लाक-आउट एक हथियार के तौर पर बार-बार इस्तेमाल किया जा रहा है छँटनी करनी हो चाहे वर्कलोड बढ़ाना हो, मजदूरों को दबाने के लिये मैनेजमेंट तालाबन्दी का सहारा लेती हैं। और देखने में यह आ रहा है कि मैनेजमेंटों के लिये तालाबन्दी एक कारगर हथियार साबित हो रहा है। अपने विरोधी के हथियार की काट के लिए मजदूरों द्वारा उस हथियार की ताकत तथा कमजोरियों की जानकारी लेनी जरूरी है। पिछले अंकों में हम इस सम्बन्ध में कुछ चर्चा कर चुके हैं। आज मजदूर आन्दोलन के लिये मुद्दा महत्वपूर्ण है। तालाबन्दी के सवाल पर सुझावों और विचार विमर्श का हम स्वागत करेंगे।

प्याली तालाबन्दी

हितकारी पॉट्रीज में 11 जनवरी को किया गया लाकआउट जारी है।

प्याली में इन्टक के एक गिरोह से तालमेल कर चौटाला जिन्दाबाद करने वालों ने अपना हरा झण्डा उतार कर तिरंगा लगाया। पर इससे उन्हें विशेष लाभ नहीं हुआ। अन्य की तुलना में इंटक के नाम पर काम कर रहे गिरोहों में सिर फुटैवल कुछ ज्यादा ही है। प्याली में इंटक के एक गिरोह से इंटक का ही दूसरा गिरोह अपने को असली इंटक बताकर दुकानदारी छीनने के लिए हाथ-पैर मार रहा है। तालाबन्दी की मार झेल रहे हितकारी पाट्रीज मजदूरों के कष्ट इंटकियों की इस खींचा-तान ने और बढ़ा दिये हैं।

छँटनी की बात अब इन्टकी गिरोह भी खुलेआम करने लगे हैं। एक गिरोह कहता है कि कोई छँटनी नहीं मानेंगे और दूसरा गिरोह कहता है कि मैनेजमेंट 500 मजदूरों की छँटनी की बात कर रही है पर जोर लगाकर 243 की ही छँटनी के लिए मैनेजमेंट को राजी कर लेंगे।

प्याली मजदूरों के लिए मामला बहुत गम्भीर है। इन मजदूरों के पास अब समय भी अधिक नहीं है। इंटकी गिरोहों की जकड़ से निकल कर ही प्याली मजदूर अपनी रोजी रोटी की रक्षा के लिए कदम उठा सकेंगे। इस सम्बन्ध में हितकारी पॉट्रीज के मजदूरों से विचार-विमर्श का हम स्वागत करेंगे।

बँगाल जूट "हड़ताल"

सी पी एम की सीटू और कांग्रेस की इंटक के संयुक्त नेतृत्व में पश्चिम बंगाल 49 जूट मिलों में 28 जनवरी से "हड़ताल" है। एक लाख चलीस हजार मजदूर इससे प्रभावित हैं।

1984 में भी एक ऐसी ही हड़ताल हुई थी। 84 दिन बाद बंगाल सरकार - जूट मिल मैनेजमेंट एसोसिएशन - यूनियनों के बीच एक त्रिपक्षीय समझौता हुआ था। उस समझौते की एक धारा यह थी कि जूट मिलों में काम कर रहे ढाई लाख मजदूरों की संख्या में कोई कमी नहीं की जाएगी। अब सीटू के आल - इंडिया जनरल सैक्रेटरी श्री निरेन घोष कहते हैं, "जूट मिलों के मजदूरों की संख्या ढाई लाख से घटाकर एक लाख चालीस हजार कर दी गई है जबकि प्रोडक्शन बढ़ा है इससे मजदूरों पर वर्क लोड बहुत बढ़ गया है। इस पूरे दौर में सीटू के बड़े लीडर निरेन घोष की पार्टी, सी पी एम की बंगाल में सरकार रही है। स्वयं श्री निरेन घोष बंगाल चटकल मजदूर यूनियन के अध्यक्ष भी हैं। आठ साल तक सी पी एम - सीटू को बंगाल में जूट मिलों में ढाई लाख जूट मिल मजदूरों को घटाकर एक लाख चालीस हजार करना दिखाई नहीं दिया। खैर यह क्या कम है कि इस बार रखी 43 मांगों में एक माँग यह भी रखी गई है कि 1984 के त्रिपक्षीय समझौते का पालन करते हुए बंगाल में जूट मजदूरों की संख्या ढाई लाख की जाये.....

एक फैक्ट्री के दायरे के पार जाकर उद्योग की किसी शाखा के मजदूरों की एकता सम्पूर्ण मजदूर वर्ग की एकता की राह पर एक कदम है। बंगाल में कार्यरत जूट मिलों के मजदूर कई ठोकरें खाने के बाद कई वर्ष से प्रान्त के आधार पर एकजुट संघर्ष के स्तर पर पहुँच चुके हैं। इसलिए यह "हड़ताल" भी बँगाल की "सब" जूट मिलों में एक मांग-पत्र के आधार पर एकजुट/एक मुस्त समझौते के लिए की गई थी। लेकिन 11 फरवरी को ही डेल्टा जूट मिल में अलग से समझौता कर लिया गया और मिल चालू हो गई। अब सीटू कहती है कि "डेल्टा माडल" पर ही समझौते होंगे। खैर, यह क्या कम है कि सीटू-इंटक की सरपरस्ती वाली हड़ताल में शामिल बंगाल में जूट मिलों में कार्यरत 16 अन्य यूनियनों में से चार ने डेल्टा समझौते पर दस्तखत करने से इनकार कर दिया है .....

वास्तव में बंगाल की सब जूट मिलों में यह "हड़ताल" शुरू भी नहीं की गई। सीटू ने बंगाल सरकार की भारत जूट मिल में प्रोडक्शन जारी रखने का फैसला लिया था। "सहकारी" क्षेत्र की न्यू सेण्ट्रल जूट मिल में बंगाल इंटक का बड़ा लीडर एक डायरेक्टर है इसलिए न्यू सेन्ट्रल जूट मिल को भी "हड़ताल" से मुक्त रखने का फैसला हुआ। तैयार माल के भावों में 25 प्रतिशत वृद्धि तथा तथा बच्चे माल के भाव में दस प्रतिशत की कमी की वजह से भारत जूट मिल और न्यू सेन्ट्रल जूट मिल चांदी कूट रही, "प्रायवेट" क्षेत्र की डेल्टा मिल भी 11 फरवरी से चांदी कूट रही है। खैर, यह क्या कम है कि "प्रायवेट" बनाम "पब्लिक" सैक्टरों के नाम से कार्यरत पूंजीवादी गिरोहों की खींचातान में इस समय हावी "प्रायवेट" के माहौल में सीटू-इंटक आदि छाती ठोकर बंगाल की जूट मिलों में "पब्लिक" पूंजी का समर्थन कर रही हैं .....

नेहरू वाले समाजवाद के दबदबे के दौर में भारत सरकार पूंजीवादी शोषण को सुचारु रूप से जारी रखने के लिए सीटू-इंटक;एटक एच एम एस - बी एम एस - यू टी यू सी (लेसा) आदि केन्द्रीय यूनियनों से महत्वपूर्ण मामलों में सलाह-मशविरा करती रही है। यह यूनियनें, खासकरके बड़े लीडर भारत में पूंजीवादी नीतियाँ बनाने में वजनदार भूमिका निभाते आ रहे हैं। इस रोल के एवज में यह यूनियनें तथा इनके लीडर हलवा-पूरी उड़ाते रहे हैं लेकिन गम्भीर संकट का सामना कर रही पूंजी की भारतीय इकाई के वर्तमान सरपरस्तों ने नेहरूवाद को बोरी में बन्द कर दिया है। सीटू-एटक के कर्ता-धर्ता ही नहीं, इंटक के लीडर भी यूनियनों के वजन के घटने, उनकी पूछ कम होने से चिंतित हैं। इसलिए पूंजीवादी लूट में अपनी हिस्सा - पत्ती बनाये रखने के लिए यूनियन लीडर आजकल खूब शोर मचा रहे हैं, आल - इंडिया हड़ताल कर रहे हैं। लेकिन यूनियन लीडरों की चिल्ल-पों से पूंजी की भारतीय इकाई के वर्तमान कर्ता-धर्ताओं के कान पर जूँ भी नहीं रेंग रही। केन्द्र सरकार पर असर पड़े या न पड़े, यह क्या कम है कि बंगाल की वामपंथी सरकार के सहयोग से सीटू ने इंटक को भी "प्रायवेट" पर हमले में शामिल कर लिया है.....

और हां इस "हड़ताल" से पहले इंटक के लीडर ने कहा था, "अगर गुप्तमतदान कराया जाये तो अधिकतर जूट मिल मजदूर हड़ताल केखिलाफ वोट देंगे।"

मन्दी

संकट पूंजीवादी व्यवस्था का है पर इसे मन्दी जैसे नामों के परदों से ढका जाता है। बी. बी. सी. के मुताबिक मन्दी की मार इंग्लैंड की संचार व्यवस्था की प्रमुख कम्पनी ढाई लाख वरकरों वाली ब्रिटिश टेलेकाम पर अपना असर दिखा रही है। पिछले साल ब्रिटिश, टेलेकाम ने पन्द्रह हजार नौकरियां खत्म की थी। अब कहा जा रहा है कि मन्दी गहरा रही है। इसलिए इस वर्ष ब्रिटिश टेलेकाम पच्चीस हजार और नौकरियां खत्म कर रहा है। हां, मजदूरों के साथ-साथ सुपरवाइजरों, मैनेजरों को भी निकाला जा रहा है . . . . . यहां एस्कार्टस के राजदूत प्लांट की ही तरह। मजदूरों को तो पूंजी चूसती ही है, संकट के गहराने पर अपने बच्चों को पूंजी भी निगल जाती है। कम से कम लोअर मैनेजमेंट को इस तथ्य को ध्यान में रखना चाहिए . . . .

कटलर हैमर.....

प्रथम पृष्ठ का शेष

माल मंगाने में छूट और उस माल पर टैक्सों की कमी की वजह से टेलेमैकेनिक जैसी कम्पनियों के पौ बारह हैं। लेकिन यहां उत्पादन करने वाली कटलर हैमर जैसी कम्पनियों के लिए सरकार की इस नीति से काफी दिक्कतें हैं। वैसे वित्तमन्त्री मनमोहनसिंह ने ऐसी स्थिति का सामना करने के लिए आठ माह पहले ही नोटिस दे दिया था और फिर सरकार ने मैनेजमेंटों को बहुत सी रियायतें दी हैं तथा आने वाले दिनों में ऐसी छेरों और रियायतें देने का खुला एलान किया हुआ है। कुछ समय से जगह-जगह मैनेजमेंटों द्वारा छटनी और वर्कलोड में वृद्धि की रफ्तार में आई तेजी मैनेजमेंटों द्वारा अपने को चुस्त दुरुस्त करने की कोशिशें हैं।

विदेशी मुद्रा की तंगी की वजह से लगे नियंत्रणों के दौरान चाँदी कूटने में लगी कटलर हैमर मैनेजमेंट के लिए अब ऐसे कदम उठाना जरूरी हो गया जिनके द्वारा वह नई हालात में काफी तेज होती होड़ में टिक सके। इसके लिए इस समय जल्दी से मजदूरों को दबाना / कुचलना मैनेजमेंट की सर्वोपरि जरूरत बनी है।

हालात कटलर हैमर के मजदूरों के लिए गम्भीर बन रहे हैं। मैनेजमेंट आने वाले दिनों में मजदूरों पर बड़े हमले करेगी। इसलिए बेबात की बातों में उलझने से कटलर हैमर मजदूरों को बचना चाहिए। फैक्ट्री और उद्योग की शाखा की स्थिति की जानकारी रख कर ही मजदूर सम्भावित हमलों का मुकाबला कर कर पायेंगे। इस सम्बन्ध में कटलर हैमर के मजदूरों से विचार-विमर्श का हम स्वागत करेंगे।

[२ मार्च को कटलर हैमर फैक्ट्री में काम शुरू हो गया है।]

किताबें

1. सचेत मजदूर का क . ख . ग

भारतीय उपमहाद्वीप को केन्द्र में रखकर इतिहास की भौतिवादी व्याख्या का एक प्रयास।

50 पेज 5/-

2. रोजा लुक्जेम्बर्ग : रूसी क्रान्ति

स्पार्टाकस प्रकाशन - अरविन्द घोष

पेज 45 11 चाणक्य

7/- 341, लक्ष्मी नगर

नागपुर-440022

3. प्रेस में : मजदूर आन्दोलन की एक झलक

फरीदाबाद मजदूर समाचार (1987 - 91) संकलन

4. Rosa Luxeburg-The Accumulation of Capital

An abridged Version with an introduction by Kamunist Kranti

240 Pages 30/-

स्वत्वाधिकारी, प्रकाशक एवं सम्पादक शेर सिंह के लिए उत्तरांचल प्रिन्टर्स, फरीदाबाद से मुद्रित